

भारत में जाति - राजनीति

भारत में जाति - राजनीति संबंध का ऐतिहासिक विश्लेषण →

- २००२ में राष्ट्रीय आयोग ने निर्वाचन में सुधार हेतु एक रिपोर्ट दी, जिसमें जाति आधारित चुनाव अभियान को रोकने की सिफारिश की गयी।
- २००७ में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की चौथी रिपोर्ट में, प्रशासन में जातिवाद को रोकने पर बल दिया गया।
- २०१३ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा राजनीतिक दलों को जातीय आधार पर रैली निकालने को रोकने का आदेश दिया गया।

उत्तर भारत में जाति- राजनीति संबंध →

उत्तर भारत की सामाजिक संरचना-

- समाज अगड़ी त्वं पिछड़ी जातियों में विभक्त ।
- 1945-1970 के काल में उच्च जातियों का राजनीतिक सशक्तिकरण ।
- 1970 के बाद मध्यवर्गीय जातियों का राजनीतिक सशक्तिकरण ।
- 1980-1990 तक दलित जातियों का राजनीतिक सशक्तिकरण ।
- 1990-2020 तक बिखराव का काल ।

भारत में जाति-राजनीति संबंध का

अर्थ →

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राजनीति का जाति पर प्रभाव और जाति का राजनीति पर प्रभाव की जाति-राजनीति संबंध की संज्ञा दी जाती है।

भारत में जाति-राजनीति संबंध का

स्वरूप →

भारत में जाति-राजनीति संबंध को दो रूपों में देखा जा सकता है -

- (i) राजनीति में जाति
- (ii) जाति में राजनीति

राजनीति में जाति →

राजनीतिक दलों द्वारा सत्ता प्राप्ति हेतु राजनीति में जाति का प्रयोग, जैसे -

- विशेष जाति के आधार पर राजनीतिक दलों का निर्माण।
- विशेष जातियों को, उनके हितों को पूरा करने का वायदा।
- जातीय आधार पर टिकट का बंटवारा।
- चुनाव जीतने के लिए जातीय समीकरणों का निर्माण।
- सरकार में जातीय आधार पर मंत्रियों को प्रतिनिधित्व।
- राजनीति में जातिवाद अर्थात् सरकार द्वारा विशेष जातियों को सरकारी लाभ प्रदान करना।

जाति में राजनीति →

अर्थात् जनता द्वारा सामाजिक - आर्थिक

हितों की पूर्ति हेतु राजनीति में जाति का प्रयोग, जैसे -

- आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने हेतु दबाव समूह के रूप में जाति संगठनों (Caste Association) का निर्माण (जैसे- जाट महासभा, गुर्जर महापंचायत आदि)।

- आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने हेतु जातीय संघों का निर्माण (जैसे- अखिल भारतीय वैश्य महासभा, अखिल भारतीय यादव महासभा आदि)।

- जनता द्वारा जातीय आधार पर राजनीति में सहभागिता।

जातीय - राजनीति संबंध के दानि/ नकारात्मक पक्ष/ विपक्ष में लके →

- राजनीति में तथा समाज में, जातीय निष्ठा को विकसित करके जातिवाद को बढ़ावा और आधुनिक समाज का निर्माण बाधित।
- राजनीति में जातिवाद से विकास की प्रक्रिया बाधित।
- विभिन्न जातियों के मध्य नकारात्मक प्रतिस्पर्धा से जाति संघर्ष एवं जातीय तनाव में वृद्धि - फलतः सामुदायिक सौहार्द्रता कमजोर।
- बहुसंख्यक संख्यक एवं प्रभु जातियों (Dominant Caste) द्वारा अल्पसंख्यक जातियों के हितों का दनन करके, समतामूलक समाज के निर्माण की प्रक्रिया बाधित।

- राजनीति में गुटबंदी एवं राजनीतिक आस्थिरता-
फलतः लोकतंत्र कमजोर ।

विचारधारा पक्ष :-

KGS



IAS